

# यूपी के 220 नगर 5 वर्षों में बनेंगे स्मार्ट, सीएम योगी ने नगर विकास सेक्टर के प्रेजेंटेशन में दिए महत्वपूर्ण निर्देश



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास सेक्टर के चार विभागों की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों का अपना घर का सपना पूरा किया है। छह माह में 2.51 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य होगा।

**लखनऊ [राज्य ब्यूरो]**। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करवाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब 220 नगरों को भी स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार इन छोटे नगरों को पांच वर्षों में चरणवार स्मार्ट बनाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर छोटे नगरों में भी विकास करें। सभी नगरीय निकायों में 'हर घर नल' के संकल्प के साथ चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाए। दो वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास सेक्टर के चार विभागों (आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव) की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों का 'अपना घर' का सपना पूरा किया है। छह माह में 2.51 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य होगा।

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 24 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। राज्य की जीडीपी में इनका 65 प्रतिशत योगदान है। स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त शहर, उच्चस्तरीय आधुनिक नगरीय सुविधाएं एवं ई-गवर्नेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नगर नियोजन करते समय हमें भविष्य की जरूरतों और जन आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के तहत महानगरों की भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआइएस) आधारित महायोजना तैयार की जाए। हर जनपद या विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टाउन प्लानर या प्रोफेशनल से ही कराया जाए। अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या बनता है।

उन्होंने कहा कि दो वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से संबंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि दो वर्षों में सभी नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषदों में भी शत- प्रतिशत आनलाइन म्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार की जाए। नगरीय निकायों में सभी नागरिक सेवाओं को पूरी तरह आनलाइन किया जाए। लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। समस्त स्थानीय निकायों में आनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम विकसित किया जाए। सभी नगर पालिकाओं को सेप्टेज प्रबंधन की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। कान्हा गोशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए।

वाराणसी, मीरजापुर और चित्रकूट में रोप-वे सेवा को यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। आगरा मेट्रो सेवा दो वर्ष में शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां इको टूरिज्म की असीम संभावना है। इन संभावनाओं को आकार देने के लिए इको टूरिज्म बोर्ड के गठन पर विचार किया जाए। लखनऊ स्थित कुकटैल पिकनिक स्पॉट को और बेहतर पर्यटक स्थल बनाने के प्रयास हों।

**अयोध्या बनेगी 'क्लाइमेट स्मार्ट सिटी'** : मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए हमें जरूरी प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में अयोध्या को 'क्लाइमेट स्मार्ट सिटी' का स्वरूप दिया जा सकता है। यह प्रयास अन्य नगरों के लिए अनुकरणीय होगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप, अयोध्या से संबंधित विकास कार्यों का शुभारंभ यथाशीघ्र कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ 2019 को पूरी दुनिया ने देखा है। अब महाकुंभ 2025 समीप है, तो लोगों की हमसे अधिक अपेक्षाएं होंगी। इसका ध्यान रखते हुए 2025 महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जाए।

## 100 दिनों में ये होंगे काम

- सभी नगर निगम वाले शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के ठोस प्रयास
- 14 नगरों में संचालित इलेक्ट्रिक-बसों की फ्लीट होगी दोगुना
- स्थानीय मांग के अनुसार नए रूट पर भी चलेगी सिटी बस सेवा
- सिटी बस सेवा को मोबाइल एप से जाएगा जोड़ा
- मिशन पिक टायलेट के तहत महिलाओं की सुविधा के लिए बनेंगे 10 हजार नए प्रसाधन
- शहरों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य में होगा सुधार

## छह महीने में ये होंगे काम

- गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना के कार्यों का शुभारंभ
- काशी, मेरठ, बरेली, झांसी एवं प्रयागराज में मेट्रो लाइट या मेट्रो नियोजन परियोजनाओं के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी/ डीपीआर होगी तैयार
- सभी नगर निगमों में शत-प्रतिशत आनलाइन म्यूटेशन
- वाटर और सीवर कनेक्शन के लिए पूरी तरह आनलाइन सेवा